जरूरत है जागने की, भ्रष्टाचार को मिटाने की

www.SaraSach.com

सारा सच अपडेट

सच्ची बात

fnYyh l; idkf'kr fgUnh ikf{kd lekpkj i=

◆वर्ष : 6 ◆अंक : 9 ◆16 जून से 30 जून 2017 ◆पृष्ठ:8 ◆मूल्य:3 रुपए हिजरी 1438 RNI NO. DELHIN/2012/41828

पशु ब्रिकी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज गोवध कानून के खिलाफ हैदराबाद स्थित एनजीओ की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक गोवध कानून को पशू बाजारों में जारी अनियमितताओं को दूर करने को लेकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य मवेशियों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाना नहीं है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर. के. अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की वेकेशन बैंच मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी करते हुए सरकार से 11 जुलाई तक जवाब देने को कहा। हालांकि पशु बिक्री अधिसूचना पर केंद्र सरकार को से राहत ही मिली है, क्योंकि कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि मोदी सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 25 मई को नया गोवध कानून लाया गया, जिसके तहत गाय और भैंस के वध पर पर रोक लगा दी गयी। केंद्र के इस आदेश के खिलाफ हैदराबाद के वकील फहिम कुरैशी ने दायर की गयी। फाहिम के मुताबिक सरकार का गोवध को लेकर जारी किया गया नया नियम संविधान के अनुरुप नहीं है। यह पूरी तरह से किसानों और व्यापारियों का रोजगार छीनने वाला है। फहीम का मानना है कि केंद्र के आदेश से एक लाख करोड़

'k"k i"B pkj ij

किसानों को भड़का रही है कांग्रेसः अमित शाह

रायपुर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि भाजपा की सरकारों में किसानों की आय दस गुना तक बढ़ी है। हमने स्वामीनाथन आयोग की कई सिफारिशें पहले ही लागू कर दी हैं। कांग्रेस किसानों की भावना भड़का रही है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। कितने भी आंदोलन हो जाएं, भाजपा आपातकाल नहीं लगाएगी।

रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस में शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन साल में भारतीय लोकतंत्र को परिवर्तित कर दुनिया में भारत की साख बढ़ाई है। मोदी ने जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी। अब पॉलीटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग है। छत्तीसगढ़

में किसानों का एक–एक दाना धान सरकार खरीद रही है।

धान का बोनस देने पर भी विचार चल रहा है। एक सवाल के जवाब में शाह ने कहा अभी भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि जब मोदी ने सत्ता संभाली थी, तो जीडीपी 4.4 फीसदी थी, अब सात फीसद है। भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। शेयर बाजार ने 31 हजार अंकों की रिकॉर्ड छलांग लगाई है।

बेनामी संपत्ति कानून यूपीए ने बनाया पर इसे लागू नहीं कर पाए।हमने इच्छा शक्ति दिखाई।

शाह ने कहा, हमने जो किया है, उसे हम बोलें यह ठीक नहीं, पर चुनाव दर चुनाव भाजपा की सफलता से यह साफ है कि हमारे काम को जनता का प्यार मिल रहा है।

पीडब्ल्यूडी ने दिया 'आप' को 27 लाख चुकाने का नोटिस

नई दिल्ली । फरवरी–मार्च में हुए गोवा–पंजाब विधानसभा चुनाव में हारने के बाद फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव में शिकस्त खाने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली में सत्तासीन अरविंद केजरीवाल सरकार पर विरोधी तो विरोधी अपने (कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास) भी हमलावार हैं। इस बीच ताजा मामले में दिल्ली सरकार के ही पीडब्लयूडी विभाग ने आम आदमी पार्टी को उनके राउज एवेन्यू स्थित दफ्तर को लेकर नोटिस भेजा है।विभाग ने अपने नोटिस में ।।च को 27 लाख रुपये का किराया चुकाने को कहा है इसके अलावा पार्टी को दफ्तर खाली करने को भी कहा गया है। वहीं, आप मुखिया अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही अपनी पार्टी को नोटिस भेजा है और पार्टी को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हज़ार रुपये चुकाने को कहा है। पीडब्ल्यूडी ने यह नोटिस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता के नाम से भेजा था। इस नोटिस में साफ लिखा है कि किसी भी प्रावधान के तहत अवैध कब्जे को आधिकारिक रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है। पार्टी ने जितने दिनों

तक इस जगह पर अवैध रूप से कार्यालय संचालित किया है इसका जुर्माना देना होगा। यहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पीडब्ल्यूडी

'k"k i"B pkj ij

संदीप के बयान पर शीला दीक्षित ने मांगी माफी

नई दिल्ली । दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने बेटे संदीप दीक्षित द्वारा सेना प्रमुख पर दिए गए विवादास्पद बयान पर दुख व्यक्त करते हुए माफी मांगी है। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने निजामुद्दीन स्थित उनके आवास पर पहुंचकर संदीप दीक्षित के बयान पर अपना विरोध जताया।

प्रतिनिधिमंडल में 30 से अधिक पूर्व सैनिक शामिल थे। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अध्यक्ष मेजर जनरल सतबीर सिंह के नेतृत्व में पहुंचे पूर्व सैनिकों की मुलाकात संदीप दीक्षित से नहीं हो पाई, लेकिन उनसे शीला दीक्षित मिलीं।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुदेश गोयत ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद कर्नल की बेटी हैं। उनके मन में सेना के प्रति बहुत सम्मान है। संदीप के दिए बयान पर उन्हें दुख है, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं थी। बता दें कि पूर्व सांसद संदीप दीक्षित द्वारा सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहें जाने पर चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है।

भाजपा सरकार ने निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाईः अजय माकन

çn'ku d ckn mifLFkr dkxl h urkvk o dk;drkvk dk lEckfèkr djr vt; ekdu

नई दिल्ली । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मोदी सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसान वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु वहां की भाजपा सरकार ने निहत्थे किसानों पर गोलियां चलवाई।

इससे पांच किसानों की मौत हो गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन किसानों के घर अपनी संवेदना जताने गए तो पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद राहुल गांधी मोटर साइकिल से मृत किसानों के परिवारों से मिलने गए थे। माकन प्रदेश कांग्रेस की ओर से बवाना में आयोजित धरने में शामिल लोगों को संबोधित कर रहे थे। माकन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी हमेशा किसानों, मजदूरों व आदिवासियों की लड़ाई न सिर्फ संसद में, बल्कि सड़क पर भी लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वे किसानों की लड़ाई को राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे।

माकन ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार व केंद्र सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने का श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार दिल्ली में लैंड पूलिंग पालिसी लेकर आई, जबकि इन दोनों सरकारों ने इस पॉलिसी को दिल्ली में लागू करने में देरी की।

कांग्रेस ने ही दिल्ली में किसानों के मुआवजे की राशि भी बढ़ाई थी।

दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों से किए गए वादे नहीं निभाए। अब किसानों ने मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो भाजपा सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी।धरने में माकन के अलावा दिल्ली प्रभारी पीसी चाको, पूर्व सांसद सज्जन कुमार, पूर्व मंत्री डॉ.नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार, बलराम तंवर, भीष्म शर्मा, विजय लोचव, डॉ.बिजेंद्र सिंह, चरण सिंह कंडेरा व हरिकिशन जिंदल आदि नेता भी शामिल हुए।

संपादकीय

&lyhe vgen

यूपी में बढ़ते अपराध जिम्मेदार कौन?

जब जब अपराध बढ़ता है तब तब अंगुलियां पुलिस पर उठती है। सच में अगर देखा जाय तो पुलिस अपनी आदत और पूर्व से चली आ रही परिपाटियों की वजह से बदनाम होती जा रही है। जो भी हो, पुलिस महकमा कभी अपनी छवि नहीं बदल पाएगा क्योंकि कुछ दाग ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं। सामाजिक समरसता, शांति, कानूनराज कायम करने अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाकर नागरिकों को सुरक्षा का अहसास कराने में पुलिस की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की कार्यशैली का सीधा प्रभाव सरकार की छवि पर पड़ता है। चुनाव के समय पुलिस की कार्यशैली ही चुनावी मुद्दा बनती है। अगर पुलिस न्यायप्रिय अपराध नाशक होती है तो रामराज्य की कल्पना साकार होने लगती है। पुलिस जब राग द्वेष से ग्रस्त होकर स्वार्थ में कार्य करती है तो खाकी वर्दी दागदार होने लगती है। चुनाव के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि हर स्तर पर बदलाव परिलक्षित होगा। बदलाव तो हर स्तर पर दिखाई देने लगा लेकिन पुलिस में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। योगी सरकार का असर हर तरफ दिख रहा है लेकिन अपराधों में कमी नहीं आ पा रही है जो चिंता का विषय है। जनवरी से अबतक जो आंकड़े सामने आये हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि हमारी पुलिस अपराधों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है।

अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाय तो जनवरी में डकैती की सोलह घटनाएँ हुयी थी किन्तु मार्च में यह बढ़कर तेइस हो गयी जबकि अप्रैल में छलाँग मारकर तैंतीस हो गयी है। इसी तरह जनवरी में लूट की दो सौ उन्चास तो मार्च में बढ़कर चार सौ इक्कीस हो गयी तथा अप्रैल में चार सौ बारह हो गयी है। जनवरी में हत्या की दो सौ छियासी घटनाएँ हुयी थी लेकिन मार्च इनकी संख्या बढ़कर तीन सौ छियान्नवे हो गयी। अप्रैल में हत्या की घटनाएँ बढ़कर तीन सौ निन्नावे हो गयी हैं।

संगीन अपराधों की श्रेणी में आने वाले बलात्कार की घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाई जाय तो जनवरी में दो सौ चौवालीस घटनाएँ हुई थी जबकि मार्च में इनकी संख्या बढ़कर तीन सौ अठहत्तर हो गयी और अप्रैल में संख्या छलाँग लगाकर तीन सौ छियान्नवे पहुंच गयी है। कहने का मतलब यह अपराध के मामले में जबसे योगी सरकार का गठन हुआ है तबसे वृद्धि होना जारी है। पुलिस की कार्यशैली में अन्य विभागों की अपेक्षा सुधार नजर नहीं आ रहा है जबकि पुलिस को भी दूसरे विभागों की तरह योगी के रंग में रंग जाना चाहिए था। योगी जी के शपथ लेने के बाद चलाये गये पहले एन्टी रोमियो अभियान की आड़ में जो तमाशा पुलिस ने शुरू किया था, उससे रोमियो का कम, भले लोगों का पार्को व अन्य सार्वजनिक जगहों पर में बैठना जरूर दूर्भर हो गया था। कुशल तो यह था कि योगी जी को समय रहते इसका पता चल गया और उन्होंने समय रहते नकेल कस दी। योगी सरकार के गठन के बाद यह सही है कि अराजकता की घटनाओं में थोड़ी वृद्धि हुई है जिन पर योगी जी सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुये कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दे चुके हैं। पुलिस प्रशासन में व्यापक फेरबदल भी किया जा रहा है किन्तु फेरबदल समस्या का निदान नहीं है। सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा।जब भी कोई नयी सरकार आती है, तब समाज विरोधी तत्व सरकार के रंग में रंगकर रंगबाजी या अपराधिक कार्यवाही करने लगते हैं। इसका सीधा असर सरकार पर पड़ता है और सरकार के साथ साथ पार्टी बदनाम होने लगती है और विरोधियों को विरोध करने का अवसर मिल जाता है। पुलिस अगर न्यायप्रिय हो जाय तो समाज की तमाम समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जाय क्योंकि पुलिस लोकतांत्रिक प्रणाली के सभी अंगों से जुड़ी होती है और उसका हस्तक्षेप होता है। पुलिस की कार्यशैली पर अगुंली उठाने से पहले यह भी देख लेना उचित होगा कि पुलिस अपने उत्तरदायित्यों का निर्वहन अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं कर पा रही है?

जरूरत है जागने की, भ्रष्टाचार को मिटाने की

भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार

भ्रष्टाचार से आज हर कोई आजिज आ चुका है जिसका सीधा आरोप सरकार पर लगाया जाता है चाहे वो किसी की सरकार हो। यह एक ऐसा रोग कह सकते है जिसका इलाज इतनी आसानी से नहीं हो सकता। भाजपा की सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है और कुछ मामलों में काम शुरू भी हो चुका है लेकिन पूरा सुधारने के लिए समय, सहयोग चाहिए जिसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है। एक बात और, जब तक हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तैयार नहीं होगे, तब तक तो कत्तई नहीं। शुरूआत हमें अपने आप से करनी होगी।

भ्रष्टाचार आज समाज में शिष्टाचार बन गया है। भ्रष्टाचार के बिना आजकल कोई कार्य होना कठिन होने गया है। भ्रष्टाचार सरकार व समाज में ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है। जो भ्रष्टाचार से दूर हैं वे समाजिक परिदृश्य से गायब हैं और उन्हें हीन भाव से देखा जाने लगा है। कहावत है कि जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है राजा के आचरण का असर सीधे प्रजा पर पड़ता है। इसी तरह घर का मुखिया अगर शराब पीता है उसके परिवार के लोग भी शराब नहीं तो भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट जरूर पियेगें।

हमारे देश में भ्रष्टाचार की शुरूआत सरकार और सरकारी कारकुनों से होती है। सरकार अगर विश्व बैंक से विकास के नाम पर कर्ज लेकर मौज मस्ती करती है तो जनता भी बैंक से कर्ज लेकर भविष्य की चिंता किये बगैर गुलछर्रे उड़ाती है।

राजनीति में घुसना हो तो बिना पैसा खर्च किये घुस पाना मुश्किल है। बिना भ्रष्टाचार का सहारा लिये बगैर कोई पद पाना आज के दौर में असंभव है। भ्रष्टाचार का सहारा लिये बगैर चुनाव जीत पाना कठिन है। सरकार बनाने के लिये विधायकों सांसदों की पूर्ति बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं रह गयी है। विधायक सांसद मंत्री बन जाने के बाद बिना भ्रष्टाचार का सहारा लिये अगला चुनाव लड़ पाना आसान नहीं है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की भूमिका अहम है और बिना भ्रष्टाचार का सहारा लिये नौकरी पाना आसान नहीं रह गया है जो पैसा खर्च करके नौकरी पाता है वह उसकी भरपाई नौकरी से करके भ्रष्टाचार को नीचे तक पहुँचा देता है।

थाना, तहसील, ब्लाक, बैंक, अदालत अस्पताल ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो और बिना पैसा खर्च किये काम हो जाता हो। बिना पैसा खर्च किये कार्य में हजार खामियां पैदा हो जाती हैं और वहीं पर जब भ्रष्टाचार का सहारा ले लिया जाता है तो सारी खामियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जो कार्य छः महीने में बिना पैसा दिये नहीं हो पाता है, वह छः घंटे में हो जाता है। उद्योगपति थोक विक्रेता को दो रूपये का सामान चार का देता है तो थोक विक्रेता उसे फुटकर विक्रेताओं को आठ का देता है और भ्रष्टाचार की बेल अपने में सबको समेत लेती है।

डीजल पेट्रोल किरोसिन डिपो से कम मिलता है और वहाँ से पेट्रोल पम्प तक कम ही होता रहता है। इस भ्रष्टाचार का सारा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब तक सेना व न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त मानी जाती थी लेकिन अब वह भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ गये हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सत्ता संभालने के बाद से ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की मुहिम चलाई जा रही है लेकिन मुहिम का असर भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों पर कम ही पड़ रहा है। नोटबंदी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिनके लिये योजना लागू की गयी थी वे कहीं सिर पीटते नहीं दिखे लेकिन आम जनता लाइन में परेशान जरूर दिखी।

lkjk lp viMsV ds lfØ; ys[kd

vfer R;kxh	शेरकोट
शाहजहापुर, (यू.पी.)	Mk- unyky Hkkjrh
nhfIr 'kek	इंदौर, (मप्र)
आगरा (यू.पी.)	dYiuk lekuh
iue 'kDyk	नवी मुंबई
गुड़गांव	drh e[kth
Mk- uhjt Hkkj}kt	लखनऊ (यूपी)
दिल्ली	ikt JhokLro
r'kkj jkt jLrkxh	सिहोर (मप्र)
दिल्ली	'kf'k JhokLro
foHkkjkuh JhokLro	नई दिल्ली
बेगुसराय (बिहार)	Mk- i#'kksÙke eh.kk
j[kk tk'kh	if.kek 'kek
फरीदाबाद	मुरादाबाद (यूपी)
Hkkouk flUgk	vuekey 'kek
गया (बिहार)	बागपत (यूपी)
Lkyhek vkfjQ	d-lh- oek
जकिर नगर	पटियाला
Lkèkk jkt	lkftn vyh खुरेजी

आखिर कब तक ?

'kcue [kku

1. यदि आप शासनिक स्तर पर न्याय चाहते हैं।
2. यदि आपकी पुलिस या अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
3. यदि कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी काम के बदले आपसे रिश्वत मांग रहा है।
4. यदि कोई आपका शारीरिक एवं मानसिक रूप से शोषण कर रहा है।
5. यदि आप जीवनसाथी या किसी अन्य संबंधी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं।
6. यदि किसी कार्यरत महिला/पुरुष का कार्यालय में अन्य तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से शोषण हो रहा है।
7. यदि किसी बुजुर्ग को परिवार में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है।
8. यदि किसी शिक्षण संस्थानों में छात्र अथवा छात्राओं का मानसिक या शारीरिक स्तर पर शोषण हो रहा है।
9. यदि कोई आपको बाल मजदूरी के लिए बाध्य कर रहा है।
10. यदि शिक्षण संस्थानों द्वारा आपसे डेवलपमेंट चार्ज या डोनेशन के नाम पर अवैध धन वसूला जा रहा है।
11. यदि उपभोक्ता किसी सेवा या उत्पाद से संतुष्ट नहीं है।
12. यदि सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में आपकी देख रेख उचित रूप से नहीं हो रही है तो घबराए नहीं, सम्पर्क करें:-

Miss Shabham Khan (President)
(Human Rights Activist)
EK Koshish Aur Abhi (EkAA) N.G.O.
Dedicated to Human Rights & Social Justice
E-mail :Khanshabnam.humarightactvist@Yahoo.in
www.ekkoshishaurabhi.org

pqIih rksMs

यदि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग कर रहा है या कोई भी विभागीय अधिकारी आपका आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण करता है या फिर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत है तो कृपया अपनी शिकायत/जानकारी पर हमें लिख भेजें। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपकी इच्छानुसार आपका नाम व पहचान गुप्त रखी जाएगी।

&fy[ks&

e[; lEikndd % lyhe vgen

सारा सच अपडेट

12@596 xyh ucj% 2] oLV x: vxn uxj]
y{eh uxj] fnYyh&110092

E-mail : sarasach99@gmail.com

lkjk lp ¼viMsV½

ikf{kd fgUnh lekpkj i=

&e[; lEiknd&
सलीम अहमद

&lg lEikndd&
उमेश कुमार झा
शाहनवाज सिद्दीकी

&lykgdkj&
दीपक त्यागी (एडवोकेट),
प्रदीप महाजन (आईएनएस),
डा. पी एल पलटा,
मनोज कुमार खत्री

&Nk;kdkj&
सुधीर कुमार, साजिद अली

C;jk@foKkiu ifrfufèk
&fnYyh&
रविन्दर कुमार,, एस सिद्दीकी,
अशफाक अली

&jktLFkku&
जयपुर–विशाल चौहान

&fgekpy insn'k&
शिमला
शान मो. खान

&mÙkj insn'k&
आगरा–हसीब हुसैन
अलीगढ़–मो. फरूख
फिरोजाबाद–फैसल मसरूर
मुज्जफर नगर–मो. इलियास

पानी चोरी की हो सीबीआइ जांच: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली । भाजपा ने आरोप लगाया कि जिस पानी से दिल्लीवासियों की प्यास बुझनी चाहिए वह टैंकर माफिया चोरी कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री भी यह स्वीकार कर रहे हैं रास्ते में लगभग आधा पानी गायब हो जाता है। यह गंभीर मामला है इसलिए इसकी जांच जरूरी है।

उन्होंने उपराज्यपाल से इसकी सीबीआइ जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड 900 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन ट्रीट करता है, जिसमें से मात्र 450 से 500 मिलियन गैलन पानी ही प्रतिदिन उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि लगभग आधा पानी कहां जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को आशंका है कि यह पानी टैंकर माफिया चोरी कर रहे हैं। जबकि सरकार टैंकर माफिया को खत्म करने का दावा करती रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार जब पानी गायब होने की बात मान रही है तो

फिर वह इसकी जांच क्यों नहीं करा रही है। इसलिए पानी चोरी के लिए वह भी दोषी है। मुख्यमंत्री को दिल्लीवासियों विशेषकर झुग्गी बस्तियों तथा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से माफी मागनी चाहिए, जिनके हिस्से का पानी मार्ग में ही गायब हो जाता है।

उन्होंने कहा कि लगभग आधा पानी रास्ते में ही गायब होने और चार सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को 178 करोड़ रुपये का लाभ होने का दावा किया जा रहा है।

दरअसल लाभ दिखाकर पानी की चोरी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सीबीआइ जांच हो तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।

उच्च पदों पर निजी क्षेत्र से टैलेंट ला रही सरकार

नई दिल्ली। सरकारी कामकाज को प्रभावी बनाने और शासन में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उच्च स्तरीय पदों पर निजी क्षेत्र से टैलेंट भर्ती कर रही है। इसका ताजा उदाहरण केंद्र के महत्वाकांक्षी अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक पद का है। सरकार ने रामनाथन रमणन को अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक नियुक्त किया है जो जानी मानी निजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत थे।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने बताया कि रमणन की नियुक्ति अतिरिक्त सचिव के स्तर पर की गयी है लेकिन सरकार वेतन और भत्ते नहीं देगी। उन्हें वेतन और भत्ते टीसीएस से ही मिलेंगे। हालांकि सरकार उन्हें आवास और यात्रा जैसी सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी।

कांत ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र से टेलेंट लाया जाए, इसी के तहत यह विशेष कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और उच्च पदों पर भी सरकार में ऐसी नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं।

डेंगू व चिकनगुनिया पर हाईकोर्ट सख्त

तीनों निगम कमिश्नरों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। डेंगू व चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए तीनों एमसीडी के कमिश्नरों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कमिश्नरों को 21 जून को पेश होने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार कहने के बाद भी डेंगू व चिकनगुनिया को रोकने की तैयारियां नहीं की गईं है। एमसीडी के वकीलों को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि झूठे हलफनामों पर क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला शुरू करें। फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि मानसून की तैयारियों को लेकर सभी पक्ष अपनी तैयारियों में तेजी लाएं।

कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों के रुके हुए वेतन पर भी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट स्वत संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट पिछले एक महीने में करीब आधा दर्जन से जयादा बार सुनवाई कर चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार

और सिविक एजेसियों की तैयारियों से अभी भी नाखुश है। 21 जून को मामले की अगली सुनवाई : सरकार और एमसीडी को भी कोर्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है जिसमें ये साफ हो कि किस कर्मचारी ने किस घर में फॉगिंग की है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को करेगा।

शहीद जवानों के परिवारों के लिए नायडू ने राजनाथ को सौंपा एक करोड़ का चेक

नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने आज केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उन्हें एक करोड़ का चेक प्रदान किया। यह चेक भारत के वीर ऐप के जरिए शहीद जवानों के परिवारों की सहायता राशि कोष में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन की ओर से दिया गया है।दरअसल वीर ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप भारत सरकार की ओर से अभिनेता अक्षय कुमार की सलाह पर शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते अप्रैल माह में जवानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई संबंधित वेबसाइट का उद्घाटन किया था। एक करोड़ रुपए के सहयोग के लिए उन्होंने वैंकेया नायडू और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन का आभार व्यक्त किया। भारत के वीर वेबपोर्टल और मोबाइल ऐप एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहां शहीद जवानों और उनके परिजनों से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद रहती है। शहीद के परिवार जन का बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर भी मौजूद रहता है। ऐसे में कोई भी आम भारतीय अपनी स्वेच्छा से जवानों के परिवार जन के बैंक खाते के जरिए सीधे मदद पहुंचा सकता है। वेबसाइट पर शहीद हुए सैनिक की शहादत से जुड़े अभियान की जानकारी भी दर्ज होगी। भारत के वीर ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के वीर नाम के पोर्टल के जरिए भी शहीद जवानों को मदद पहुंचाने का कार्य किया जा सकता है।

ekdfVx] ,fDtD;fVo] fMLVhC;Vj rFkk
foKkiu ifrfufèk lEidZ djs

lkjk viMV dk pkfg, egurh] l?k"k"khy]
t>k: C;jk phQ ¼lHkh ftykå] lokn nkrk

पाठकों के लिए विशेष

tk Hkh ikBd vPNh dgkuh] dfork,] [kcj bR;kfn
nxk mlS ehfM;k lS tMus dk ekdk feyxk

विज्ञापन

nk dk lkFk	;k	30 ifr'kr
,d Ýh		dh NV

gekjs lekpkj i= dk tfj, viuk 0;kikj
dk c<k,¡ ;k oclkbV ij viuh
ifCyflVh djk,¡ lEidZ djs

lEidZ djs%
91-999-000-7067
www.sarasach.com
Email : sarasach99@Gmail.com

मोदी सरकार : तीन साल बाद देश कहां है

भारतीय लोकतंत्र में बड़े राजनीतिक तूफान आये हैं और निश्चित रूप से तीन साल पहले आयी 'मोदी लहर' को भी उन तूफानों में गिना जा सकता है। 2011 में अन्ना आंदोलन से उत्पन्न ज्वार को मजबूत आरएसएस और भाजपा कैडर ने बखूबी अपने पक्ष में मोड़ा, इस बात में दो राय नहीं और इसके लिए नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी एवं विकासवादी छवि ने बड़ा रोल प्ले किया था। 2014 के आम चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा सरकार सत्तासीन हुई और तबसे आज तक विपक्ष लगातार कमजोर होता गया है। तबसे लगातार बड़े–बड़े नारे गढ़े गए और एक के बाद एक ऐसी योजनाएं पेश की गयीं मानो देश अच्छे दिन की गंगा में डुबकी लगा रहा हो। एक–एक करके विभिन्न राज्यों का चुनाव भी भाजपा ने जीता, तो यह माना जा सकता है कि जनता में 'अच्छे दिन' की आस अभी बनी हुई है पर बेहद दिलचस्प रहेगा यह आंकलन करना कि 'तीन साल बाद देश कहाँ है?' जनता में नरेंद्र मोदी की असाधारण साख का कारण क्या है और क्या यह साख 2019 में बनी रह सकती है?

जाहिर तौर पर ऐसे आवश्यक प्रश्नों के बिना केंद्र सरकार के बीते 3 साल का समग्र आंकलन संभव न हो सकेगा३

घरेलु मोर्चे में राजनीतिक लोकप्रियता की बात की जाए तो तमाम चुनावों में मिली जीत, खासकर यूपी की जीत केंद्र सरकार के नंबर बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, स्टैंडअप इंडिया, उड़ान, सुरक्षा बीमा योजना, बेटी बचाओ, उज्जवला योजना, कौशल विकास योजना, जन–औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वीआईपी कल्चर खत्म करना जैसी कई योजनाओं को सीधे आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश में एक हद तक सफलता अवश्य मिली है। हालाँकि, नोटबंदी जैसे बड़े कदम उठाकर सरकार ने क्या लक्ष्य हासिल किये, यह अँधेरे में ही रहा पर दूसरी तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को कमोबेश अवश्य मिला है।

चूंकि, ये योजनाएं ऐसी हैं कि इनके क्रियान्वयन की लगातार निगरानी की आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा भ्रष्टाचार पनपेगा और मामला वहीं से खराब होना शुरू जाएगा। इसके साथ यह भी सच है कि इन योजनाओं से जिस बड़े स्तर के बदलाव की बात कही गयी थी, वैसा अपेक्षित बदलाव देखने को नहीं मिला।

इन कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो घरेलू मोर्चे पर कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी और हिंसा ने राज्य और केंद्र सरकार की खासी किरकिरी कराई है।

यूं यह समस्या कोई आज की तो है नहीं, बावजूद इसके मोदी प्रशासन को इस समस्या के बढ़ने के लिए मीडिया के एक हलके में दोष दिया जा रहा है। इसके साथ पीएम ने खुद कहा था कि 80 प्रतिशत गौरक्षक आपराधिक तत्व हैं फिर उन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कुछ खास नहीं किया जाना लोगों को खटक रहा है। इसी से जुड़ा प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि बीफ के एक्सपोर्ट पर सरकार रोक क्यों नहीं लगाती?

साथ ही साथ नक्सलवाद की समस्या और सैनिकों, केंद्रीय बलों की लगातार जा रही जान पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार की नीति आखिर क्या है इन महत्त्वपूर्ण मसलों पर।

जाहिर है, राह आसान नहीं है किन्तु देश में विपक्ष की अत्यधिक खराब हालत ने मोदी सरकार को एक तरह से तमाम घरेलू मुद्दों पर वॉक ओवर दे रखा है और फिर चाहे महंगाई बढ़े या रेल का किराया बढ़ें, केंद्र सरकार से संसद और सड़क पर मजबूती से प्रश्न पूछने वालों का अकाल सा पड़ गया है। कांग्रेस सदन में शोर जरूर मचाती है किन्तु सोनिया–राहुल के नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। ऐसे ही दूसरी तमाम पार्टियां पस्त दिख रही हैं, वह चाहे अरविन्द केजरीवाल की अगुवाई वाले 'आप' हो या कोई और।

केंद्र सरकार इस मुद्दे पर खुद को फोकस रखने को काफी प्रयासरत रही है। इसके लिए विदेशी निवेश लाने के प्रयास से लेकर, जीएसटी और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को गिनाया जा सकता है पर नोटबंदी के बाद आर्थिक मजबूती के प्रयास थमे से लगते हैं। लोग पूछते फिर रहे हैं कि सरकार ने हर साल दो करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, इस वादे का क्या हुआ? या फिर सरकार विदेशों से काला धन लाने में क्यों नाकाम रही?

या फिर सरकार ने बड़ी कंपनियों को बहुत सारी रियायतें दी हैं, फिर भी जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी सेल यूनिट को बंद क्यों कर रही हैं? नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में चीन अपने सामान ठूँसता जा रहा है, तो ऐसे में भारत की क्या रणनीति है?

ऐसे तमाम प्रश्न आधारहीन नहीं कहे जा सकते क्योंकि चुनाव जीतने के समय जनता में काफी सारी उम्मीद जगाई गयी थी। हालाँकि, वृद्धि दर को लेकर सरकार अपनी पीठ ठोक सकती है कि नोटबंदी जैसे भयानक कदम के बावजूद इंडियन इकॉनमी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, पर असर पड़ना और आगे बढ़ना दो अलग चीजें हैं। वास्तविकता यही है कि सरकार बड़ी संख्या में नौकरियाँ पैदा करने में सफल नहीं हो पा रही है।

रियल एस्टेट को गति देने के लिए सरकार ने रियल एस्टेट बिल जरूर लाया और पहले आवास पर सब्सिडी भी दे रही है, किन्तु इतना प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहा है। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम उस रफ्तार से नहीं चल रहा है, जैसी उम्मीद की गयी थी तो आईटी सर्विसेज अमेरिकी संरक्षणवाद के साये में धीमा होने को मजबूर है।देखा जाए तो सरकार के बीते तीन साल मिले जुले रहे हैं। राहत की बात यह जरूर हो सकती है कि बीते 3 साल में केंद्र सरकार में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं निकला है। नरेंद्र मोदी की साख के पीछे यह महत्त्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। कई विभागों की इस बाबत लगाम भी कसी गयी है, किन्तु मुश्किल यह है कि जनता की उम्मीदें कई गुना अधिक जगाई गयी हैं।

जिन्दा किसानों के लिये बजट नहीं, लेकिन मृत किसानों को करोड़ रुपये!

सांसद और विधायक जब चाहें तब खुद के वेतन, भत्ते और सुख–सुविधाओं में बढोतरी कर लेते हैं। घाटे में चल रही निजी कम्पनियों, उद्योग घरानों और कारपोरेट घरानों के कर्ज को मफ करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सरकारी तंत्र को जरूरत के अनुसार हर प्रकार की सुख–सुविधा प्रदान करने में सरकारी बजट में कोई कमी नजर नहीं आती है। सरकार की साम्प्रदायिक नीति के प्रचारक बाबाओं की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करने के सरकार के पास धन है।

भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान! का ओजस्वी नारा दिया था और किसान तथा जवान एकजुट होकर शास्त्री जी के साथ खड़े हो गये थे। इसी नारे को अपना समर्थन देते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने इसके पीछे जय विज्ञान जोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने, उनकी सरकार ने या उनकी पार्टी की किसी भी सरकार ने किसानों के लिये किया कुछ नहीं। हां उनकी भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार के शासन में मध्य प्रदेश में गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दर्जन किसानों की फौज के मार्फत हत्या अवश्य करवाई जा चुकी है। क्या यही जय जवान और जय किसान है। जिस भारत सरकार की फौज किसानों की हत्या कर रही है, उस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है।

फौज के हाथों मारे जा रहे किसान का अपराध क्या है?–किसान सिर्फ अपनी कृषि उपज का वाजिब मूल्य चाहते हैं। लेकिन सरकार उचित मूल्य किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहती है। इसके विपरीत क्रूर पूंजीवाद की समर्थक भाजपा की भारत सरकार कृषि आय को भी आयकर के दायरे में लाने पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तनशील है।

कृषि और किसानों की हालत में सुधार के लिये सरकार के पास बजट नहीं है, जबकि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को हर दस साल बाद वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन में बढोतरी की जाती रहती है। उन्हें साल में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। सांसद और विधायक जब चाहें तब खुद के वेतन, भत्ते और सुख–सुविधाओं में बढोतरी कर लेते हैं। घाटे में चल रही निजी कम्पनियों, उद्योग घरानों और कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज को माफ करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सरकारी तंत्र को जरूरत के अनुसार हर प्रकार की सुख–सुविधा प्रदान करने में सरकारी बजट में कोई कमी नजर नहीं आती है। सरकार की साम्प्रदायिक नीति के प्रचारक बाबाओं की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करने के सरकार के पास धन है। सरकारी शोषक नीतियों का कुप्रचार करने के लिये और मीडिया को अपना पिठ्ठू बनाये रखने के लिये विज्ञान के नाम पर मीडिया को रिश्वत देने के लिये सरकार के पास हजारों करोड़ का बजट है। मगर दुरूखद और शर्मनाक तथ्य कि कृषि संरक्षण और किसानों के आंसू पौंछने के लिये सरकार के पास धन नहीं है।

भारत के अन्नदाता किसान की बहुत छोटी सी और सौ फीसदी न्यायसंगत मांग है, (जिसे समस्या बताया जाता है) किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिलना चाहिये। यह मांग मानना सरकार के लिये आसान नहीं है। या यह कहा जाये कि किसान को फसल का वाजिब मूल्य देना सरकार की चिन्ता ही नहीं है। इसका कारण बताया जाता है, बजट का अभाव और आम गरीब लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाने की सरकारी नीति। जबकि गरीबों को सस्ती दर पर सरकार अनाज उपलब्ध करवा रही है।

इसके ठीक विपरीत किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली कृषि तकनीक, बीज और कीटनाशकों की बेतहाशा तथा मनमानी मूल्य वृद्धि करने वाली कम्पनियों को बढावा देना और उनको अनियन्त्रित छोड़ना सरकार के लिये बहुत आसान काम है। साफ शब्दों में कहा जाये तो किसान का शोषण होते तथा करते रहना ही सरकार का अघोषित ऐजेंडा है। इस शोषण के खिलाफ उठने वाली असंगठित किसानों की आवाज को दबाने के लिये फौज के मार्फत किसानों की हत्या करवाई जा रही हैं और मृतकों को चुप कराने के लिये प्रति मृतक एक करोड़ मुआबजा घोषित किया जा रहा है। जिससे मृत परिवारों को चुप करवाया जा सके!

जिन्दा किसानों के लिये बजट नहीं, लेकिन मुआबजे के लिये बजट है! यह अपने आप में हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति है! इससे भी अधिक शर्मनाक उन ढोंगी तथा नकाबपोश राजनेताओं की चुप्पी है, जो अपनी काली घ्कमाई के जरिये रैलियां और सभाओं का आयोजन करके किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनाओं के नाम पर किसानों को गुमराह करने में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन किसानों की सरकारी तंत्र द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं के समय किसी बिल में दुबके बैठे हुए हैं। सबसे पहले किसानों को ऐसे राजनेताओं को नंगा करना बहुत जरूरी है। बल्कि पहली जरूरत है। ऐसे राजनेता ही किसानों के असली दुश्मन हैं!

M,- i|#"kk|Ùke eh.kk fujd|'k&jk"Vh; çe[k gd j{kd ny ¼HRD½ lkekftd lxBu ¼jft-½

i|Fke i"B dk 'k"k

पशु ब्रिकी अधिसूचना...

सलाना करोबार वाली मीट इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। गोवध कानून को लेकर कोर्ट के बाहर भी एक लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी के तहत केरल में कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई ने गाय के बछड़े को काटकर विरोध जताया, जबकि चेन्नई आईआईटी में छात्रों ने बीफ पार्टी मनाई गयी।

पीडब्ल्यूडी ने दिया...

को एक याचिका भेज कर पार्टी के वर्तमान कार्यालय से ही काम संचालित करने की अनुमति मांगी थी। इसके जवाब में पीडब्ल्यूडी ने पार्टी को नोटिस भेजते हुए 27 लाख रुपये का जुर्माना चुकाने को कहा है। नोटिस में विभाग ने तर्क देते हुए कहा कि पार्टी को ये कार्यालय आवंटित किया ही नहीं जा सकता, उपराज्यपाल भी इसे पहले ही रद कर चुके हैं।बताया जा रहा है कि ।।च ने जल्द ही अपना पार्टी कार्यालय खाली नहीं किया तो समय बढ़ने के साथ इस राशि में इजाफा होता चला जाएगा।

दो महीने पहले यानी अप्रैल 2017 में शुंगलू समिति ने इस दफ़्तर का आवंटन अवैध करार दिया था। एलजी ने भी इस आवंटन को रद कर दिया था और च्व्क विभाग ने आम आदमी पार्टी ये जगह तुरंत खाली करने के आदेश दिए थे।

क्यों बढ़ रहे हैं महिलाओं में डिप्रेशन के मामले

–फहमीना

महिलाओं से घर वाले यही अपेक्षा करते हैं कि वह घर की सही तरह से देखभाल करे, बच्चों का ठीक तरह से लालन.पालन करे, परिवार के सभी लोगों का कहा माने और घर का स्टेट्स और बढ़ाने के लिए नौकरी भी करे। अब जब किसी महिला पर काम का इतना बोझ रहेगा और उसे घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेवारियां समान रूप से ईमानदारी के साथ निभानी हैं, तो जाहिर है कि महिलाओं में तनाव बढ़ेगा ही।

डिप्रेशन के जो कारण अमूमन देखने में आते हैं, उनमें संयुक्त परिवारों में अभिव्यक्ति की कमी महत्वपूर्ण होता है। आज के शहरी जीवन में होता यह है कि एक या दो कमरों के फ्लैट में जब पूरा परिवार रह रहा होता है, तो ऐसे में पति–पत्नी को पूरी आजादी नहीं मिल पाती जिससे अपनी कुंठा मिटाने के लिए पति कभी बच्चों की पिटाई कर देता है तो कभी पत्नी रूठ कर बिना खाना बनाए बीमारी का बहाना कर सो जाती है। कभी.कभी इस डिप्रेशन का कारण महिलाओं के साथ ऑफिस में होने वाला अभ्रद व्यवहार भी बन जाता है।दरअसल कई बार महिलाओं के समक्ष काम करने की मजबूरी होती है तो कभी

महिलाएं यह सोचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की हरकतों को सह लेती हैं कि कहीं वह उनकी गलत रिपोर्ट आगे न भेज दें।

महिलाओं का बार.बार उनकी हरकतें सहते जाना अधिकारियों के हौसले बढ़ा देता है, जिसके नतीजे कभी.कभी गलत निकल आते हैं और

;fn vki ?kj vkj v,fQl dh nkgjh ftEenkjh fuHkk jgh gS rks viuh enn ds fy, fdlh ckbZ ;k ukSdjkuh dk bartke vo'; dj ysa] ftlls vkidks v,fQl esa ?kj ds dke dh vkSj ?kj esa v,fQl ds dke dh fpark u jgsA

महिलाएं तनावग्रस्त हो जाती हैं। कई मामलों में यह भी देखने में आया है कि यदि किसी महिला को यह शक हो जाए कि उसके पति के संबंध किसी दूसरी स्त्री से हैं, तो समझिए कि उस महिला का सब सुख.चौन छिन जाता है।यदि आप घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं तो अपनी मदद के लिए किसी बाई या नौकरानी का इंतजाम अवश्य कर लें, जिससे आपको ऑफिस में घर के काम की और घर में ऑफिस के काम की चिंता न रहे। यदि आपका पति शराबी है, तो उससे रोज.रोज झगड़ने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला।

आपको चाहिए कि जब वह नशे में न हो, तब उसे प्यार से नशे के अंजाम के बारे में बताकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें।जब कभी ऐसी स्थिति आपके समक्ष आ जाए कि आपको पता चले कि आपका पति किसी और स्त्री के साथ संबंध रखता है, तो एकदम से विचलित होने की बजाय पहले इस बात की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। अपनी जान देने से कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि आपका यह कदम आपके पति को फायदा ही पहुंचाएगा।

यदि आपका पति सचमुच पराई स्त्री के साथ संबंध रखता है, तो घर के बड़े.बुजुर्गों को यह बात बता कर उन्हें ही इस समस्या का हल निकालने के लिए कहें।

इस प्रकार आप देखेंगी कि जब आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करने लगेंगी और आने वाली समस्याओं से निपटने की तैयारी पहले ही कर लेंगी, तो न सिर्फ आप डिप्रेशन से दूर रह पाएंगी बल्कि एक हंसता. खेलता जीवन भी गुजार सकेंगी।

मौसम कोई भी हो, खूब खाइए आंवला

बचपन में जब भी दादी–नानी को आंवले का मुरब्बा या आंवले का आचार लगाते देखते तो मन में शायद एक पल के लिए यह सवाल उठता कि यह आंवला इतना कड़वा और खट्टा होता है तो फिर इसका इस्तेमाल किसलिए? फिर बुजुर्ग हमें इसके फायदे बताते कि आंवला सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। आंवले को मनुष्य के लिए प्रकृति का वरदान कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे गुणकारी बताया गया है। यह कई बीमारियों को दूर करता है। इसका अपना पौष्टिक महत्व भी है। आंवला विटामिन सी का बढ़िया स्रोत माना जाता हैं। संतरे से बीस गुना ज्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता हैं।

आंवले को गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता हैं। आंवले का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसे पकाने के बाद भी इसमें मौजूद विटामिन 'सी' खत्म नहीं होता। आंवला गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में पाया जाता है। ताजे आंवले में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटिन, विटामिन सी और बी काम्पलेक्स के अलावा 80 प्रतिशत पानी पाया जाता है। इन सबके अलावा इसमें गैफिक एसिड भी पाया जाता है जिसमें पोलिफिनोल होता हैं। आंवले का इस्तेमाल आर्युवेदिक दवाइयों में ज्यादा किया जाता है।

हमारे शरीर में कॉलेस्ट्राल काफी महत्व रखता है। मनुष्य का लिवर कोलेस्ट्राल का मुख्य स्रोत माना जाता है। शरीर में उपयोग न होने वाला कोलेस्ट्राल खून की नलिकाओं में जम जाता है जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा रहता हैं।

आंवले में मौजूद विटामिन 'सी' इस कॉलेस्ट्राल को खून की नलिकाओं से घुलाने में मदद करता है जिससे शरीर का ब्लड प्रेशर कम होता है। शरीर में पैनक्रियाज का ब्लड ग्लूकोज स्तर कंट्रोल न कर पाना डायबिटिज होने का संकेत देता हैं।

आज हमारे देश में मधुमेह के मरीज बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं जो आंवला आपके लिए अचूक दवा है। आंवला, जामुन और करेले की बराबर मात्रा मिलाकर एक–दो चम्मच हर दिन लें तो यह काफी फायदा पहुंचाता है। यह आपके मधुमेह को काबू में रखने में मदद करेगा।

ज्यादा मीठा, खट्टा, तीखा और तैलीय खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा कॉफी, चाय और सिगरेट से भी एसिडिटी या गैस होने का खतरा होता है। इससे गुस्सा, दुःख और निराशा हो जाती है। जब पेट में बहुत ज्यादा जलन हो तो बस आंवला ले लीजिए। अगर जरूरत से ज्यादा एसिडिटी हो तो एक ग्राम आंवला पाउडर में थोड़ी सी चीनी मिलाकर पानी या दूध के साथ ले लें तो इससे काफी आराम मिलता है।बालों का झड़ना, बेजान व रूखे होने या उम्र के साथ सफेद होना इन सबमें आंवला बेहद फायदेमंद साबित होता हैं।

सुंदरता बढ़ाते हैं मजबूत नाखून

महिलाओं का सौन्दर्य बढ़ाने में नाखूनों का भी योगदान होता है। स्वस्थ, सुंदर और अच्छी नेल पालिश से युक्त नाखूनों की सराहना भी होती है। खूबसूरत, लम्बे और मजबूत तथा स्वस्थ नाखून किसे अच्छे नहीं लगते। लेकिन कई महिलाएं जानकारी के अभाव में नाखूनों की उचित देखरेख नहीं कर पातीं और यही सोचती रहती हैं कि काश! हमारे नाखून भी उस महिला जैसे अच्छे होते। नाखूनों की देखरेख करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना होता है यदि हम अपने सामान्य जीवन में नाखूनों के प्रति थोड़ी सी भी सावधानी बरत लें तो इनको स्वस्थ और मजबूत बनाया जा सकता है। बर्तन साफ करने से पहले हमेशा रबड़ के दास्तानें पहनने चाहिए क्योंकि पानी और डिटरजेंट के संपर्क में नाखून कमजोर हो जाते हैं। अंदर की नमी को सोखने के लिए रबड़ के दास्ताने के अंदर पतले सूती दास्तानें पहन सकती हैं। महिलाओं को नाखूनों के लिए नेलपॉलिश रिमूवर का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एसीटोन रहित होने चाहिएं क्योंकि यह नाखूनों को बहुत शुष्क कर देता है जिससे वे आसानी से टूट जाते हैं। अधिकांश महिलाओं को बागवानी का शौक होता है लेकिन अपने इस शौक को पूरा करते समय वह नाखूनों के प्रति सावधानी बरतती नहीं दिखतीं।

फादर डे : 18 जून

हैप्पी फादर्स डे

पूरे विश्व में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। भारत में भी धीरे–धीरे इसका चलन बढ़ता जा रहा है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमंडलीकरण की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है और पिता के प्रति प्रेम के इजहार के परिप्रेक्ष्य में भी।

लगभग 9108 साल पहले 91908 में अमेरिका के वर्जीनिया में चर्च ने फादर्स डे की घोषणा की थी। 11६ जून 1910 को वाशिंगटन में इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गयी। अब पिता को याद करने का एक दिन बन गया था पर क्या पिता को याद करने का भी कोई एक दिन होना चाहिए ? मुझे तो समझ नहीं आता। यह पश्चिम की परम्परा हो सकती है पर हमारे यहाँ तो नहीं।

पश्चिम में जहाँ विवाह एक संस्कार ना हो कर एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। ना जाने कब एक समझौता टूट कर दूसरा समझौता हो जाय, कुछ पता नहीं होता। ऐसे में बच्चों को अपने असली जन्मदाता के बारे में पता भी नहीं होता होगा। इसी लिए शायद पश्चिम में फादर्स डे की घोषणा करनी पड़ी होगी ताकि बच्चे अपने असली जन्मदाता को उस दिन याद करें पर हमारे यहाँ तो पिता एक पूरी संस्था का नाम है, पिता एक पूरी व्यवस्था, संस्कार है, हमारा आदर्श है।

हमारे यहाँ कोई भी संस्कार पिता के बिना संपन्न नहीं होता। वही परिवार का मुखिया होता है और परिवार को अनुशासन की डोर में बांधे रखता है। हम उन्हें एक दिन में कैसे बाँध सकते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक वजूद दिया, चलना, बोलना और हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया, उनके लिए सिर्फ एक दिन। जिनके कारण हमारा अस्तित्व है उनके लिए इतना कम समय।

मुझे याद नहीं आता कि बचपन में मैंने कोई फादर्स डे जैसा शब्द सुना था। यह अभी कुछ सालों में ज्यादा प्रचलित हुआ है जब विदेशी कंपनियों ने इस डे वाद को बढ़ावा दिया है। इतने सारे डेज की वजह से ये कंपनियां करोड़ों रूपये अंदर करती हैं और हम खुश होते हैं एक डे मना कर या शायद विदेशों की तरह हमारे यहाँ भी रिश्तों की नींव दरकने लगी है। संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है। परिवार के नाम पर पति, ,पत्नी और केवल बच्चे हैं। पिता परिवार से बाहर हो चुके हैं और हाँ, माँ भी।

पिता अकेले पड़ गए हैं। उनके बुढ़ापे की लाठी कहीं खो गयी है। है तो बस जीवनसाथी का साथ, वह भी भाग्यशाली पिता को। हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति हावी होती जा रही है। पिता के लिए घर में कोई स्थान नहीं।

वे बोझ लगने लगे हैं। इसी सोच के चलते हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां तक की वेटिंग में लंबी लाइन लगी है उनको वृद्धाश्रमों में धकेलने की।

लोग सोशल मीडिया पर फादर्स डे के दिन स्टेटस तो डालेंगे पर पिता के पास बैठने के लिए दो घड़ी का समय उनके पास नहीं है। वह कहीं अकेले बैठे होंगे कोने में। बड़े दुःख की बात है और शर्म की भी कि जिसके बिना हम अधूरे हैं, उसी को हम भूलते जा रहे हैं। अपने जीवन की सुख–सुविधा उसके संग नहीं बाँट पा रहे हैं। विदेशों में जहाँ माता–पिता को ओल्ड एज हाउस में शिफ्ट कर देने की परंपरा है, वहाँ तो फादर्स–डे का औचित्य समझ में आता है पर भारत में कहीं इसकी आड़ में लोग अपने दायित्वों से मुंह तो नहीं मोड़ना चाहते ?

अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा तो नहीं पाना चाहते ? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आज जरुरत है आगे बढ़ कर उन्हें सँभालने की, उन्हें सहारा देने की, उनको जिम्मेदारियों से मुक्त करने की। कल उन्होंने हमें संभाला था, आज हमारी बारी है, उनके अकेलेपन को कुछ कम कर पाने की, उनके चेहरे पर खुशी लौटा पाने की, उन्हें वही स्नेह लौटाने की जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है हमारे थोड़े से समय की जो उनके लिए हो। जिस दिन हम सब ऐसा करने में सफल हों जायेंगे, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से रोज थोड़ा सा समय उनके साथ बिताएँगे, उनकी परवाह करेंगे, स्वयं उनका ख्याल रखेगें, उस दिन से हर दिन होगा –– हेप्पी फादर्स डे ।

आइस स्कीइंग के लिए मशहूर, खूबसूरत औली

बद्रीनाथ धाम के निकट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है गढ़वाल का मशहूर औली क्षेत्र। यहां पर घने जंगलों के साथ ही खूबसूरत पहाड़ तथा मखमली घासों से ढंके हुए मैदान फैले हुए हैं।

देश का सबसे नया आइसस्कीइंग केंद्र भी यहीं पर मौजूद है। यहां पर आप बर्फ पर फिसलने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। बर्फ की चादरों से ढंकी यहां की खूबसूरत ढलानें एशिया की खूबसूरत ढलानों में भी गिनी जाती हैं।

यहां से आप नंदा देवी, हाथी गौरी पर्वत, ऐरावत पर्वत तथा नीलकंठ पर्वत का नजारा भी बखूबी देख सकते हैं। सबसे पहले भारत–तिब्बत सीमा पुलिस ने इसे आइसस्कीइंग खेल मैदान के रूप में तलाशा था फिर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने स्कीइंग को बढ़ावा देने की मंशा से यहां स्कीइंग केंद्र की स्थापना की। यहां पर रोपवे भी है जोकि औली के आकर्षण में अनूठा साबित हुआ है। रोपवे की रोमांचक यात्रा सैलानियों को आनंदविभोर कर देती है। जब पर्यटक इसमें बैठकर जंगल, खेत और गांवों के ऊपर से गुजरते हैं, तो उनका मन झूम उठता है।

दर्शनीय स्थलों की बात करें तो आप सबसे पहले गुरसौं बुग्याल देखने जा सकते हैं। ओक और कोनिफर के जंगलों से घिरा हुआ और खूबसूरती से भरापूरा यह मैदान सैंकड़ों मीलों तक फैला हुआ है। औली से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरसौं बुग्याल में गर्मियों के मौसम में असंख्य फूल भी खिलते हैं।

आप क्वांरी बुग्याल भी घूमने जा सकते हैं। यह एक मनोरम स्थल है। यहां पर दूर–दूर तक फैली हुई खूबसूरत ढलानें देखते ही बनती हैं। इन ढलानों पर ट्रैकिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। जोशीमठ भी औली के सर्वश्रेष्ठ दर्शनीय स्थलों में शुमार है।

औली से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित जोशीमठ में आप मठों, स्मारकों के दर्शन कर सकते हैं। यहां पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक महत्व के कई सारे मठ व मंदिर मौजूद हैं साथ ही आप यहां पर्वतारोहण भी कर सकते हैं। इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि इसे बदरीनाथ और फूलों की घाटी का प्रवेशद्वार भी माना जाता है। सेलधार तपोवन को देखने का अपना अलग ही मजा है। क्योंकि यहां पर गरम पानी के अनेक सोते हैं, जिन्हें देखते ही बनता है। यहां पर आप अधिक उबलते गरम पानी के फव्वारे और सोते को देख कर दंग रह जाएंगे।

इसी प्रकार चिनाब झील भी देखी जा सकती है। यह झील प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह जोशीमठ के पास स्थित है। लेकिन कठिन चढ़ाई होने के कारण अभी इस स्थल का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। वंशीनारायण कल्पेश्वर भी देखने योग्य जगह है, खासकर गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में यह पूरी घाटी फूलों से ढंकी हुई नजर आती है। इस मनोरम दृश्य को देखकर सभी पर्यटक आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। यदि आप औली की यात्रा करने का मन बना चुके हैं तो आपको बता दें कि यहां तक आपको सीधी रेल सेवा नहीं मिल पाएगी।

यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। आप ऋषिकेश स्टेशन से औली के लिए बस ले सकते हैं। ऋषिकेश से औली लगभग 253 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।चाहें तो ऋषिकेश से जोशीमठ तक के लिए बसों तथा टैक्सियों व जीपों का भी प्रयोग कर सकते हैं ।

lkjk lp ,d tfj;k g nfu;k dh lcl cMh ifl) lk'ky uVofdx lkbV ij viu dkjkckj dk cM y oy ij c<ku d fy, lkjk lp v[kckj@oc lkbV e foKkiu ndj viuh ifCyflVh djok, D;kfd lkjk lp u bu ij viuh ikQkby@vkbMh cukdj viuh igpku cukb g vkj ykxk dk viu lkFk tkMdj ge'kk viMV jgrk gA
lEid dj % $91&999&000&7067

E-mail : sarasach99@Gmail.com

JOIN-US Facebook Google Plus

0;kikj lekpkj

म्युचुअल फंड कंपनियों के खिलाफ शिकायतों में हुआ ४० फीसद का इजाफा

नई दिल्ली । भारत की दिग्गज म्युचुअल फंड कंपनियों के खिलाफ वर्ष 2016–17 में निवेशकों की ओर की गई शिकायतों के आंकड़ें में 40 फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बढ़कर 17,569 हो गई है। फोलियो नंबर्स में इजाफे के कारण शिकायतों की संख्या भी बढ़ी है।मुख्य रुप से निवेशकों के ब्योरे में आंकडें में सुधार और एड्रेस में बदलाव को ठीक नहीं किए जाने, पैन डिटेल्स और नामांकन व अन्य चीजों के बारें में शिकायतें सामने आईं हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिकायतें फोलियो नंबर या निवेशक खाते बढ़ने के कारण बढ़ी हैं। साथ ही निवेशकों की ओर से गलत आंकड़ें देने के अलावा उनकी ओर से आवेदन फॉर्म भरते वक्त कई गलतियों के कारण भी शिकायतें बढ़ी हैं। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के मुताबिक टॉप पांच म्युचुअल फंड कंपनियों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ, एचडीएफसी एमएफ, रिलायंस एमएफ, बिड़ला सनलाइफ एमएफ और एसबीआई एमएफ के खिलाफ पिछले वित्त वर्ष में कुल 17,569 शिकायतें मिलीं हैं। आप को बात दें कि वर्ष 2015–16 में यह आंकड़ा 12,579 था। तेलंगाना के सूचना प्राद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री टी रामाराव ने बताया है कि उनके राज्य से सॉफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2015–16 के 75,070 करोड़ रुपए से करीब 14 फीसद बढ़कर वित्त वर्ष 2016–17 में 85,470 करोड़ रुपए का हो गया है।उन्होंने कहा, तेलंगाना आईटी–आईटीईएस निर्यात में 13.85 फीसद का अच्छा इजाफा हुआ है, जो कि 10 फीसद की औसत वृद्धि दर से करीब चार फीसद ज्यादा है। यह बीते वित्त वर्ष में 85,470 करोड़ रुपए का रहा था।

सीटीआइ की जीएसटी को सितंबर से लागू करने की सलाह

नई दिल्ली। दिल्ली के कारोबारी व उद्यमी संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) ने वस्तु एवं सेवा कर को जुलाई की जगह सितंबर से लागू करने की मांग की है। इसके अलावा जीएसटी की प्रस्तावित दरों में भी कटौती का सुझाव दिया है। सीटीआइ के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता में दिल्ली के विभिन्न वस्तुओं और थोक बाजारों से जुड़े कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल को सुझाव भेजे गए हैं।सीटीआइ के संयोजक बृजेश गोयल और हेमंत गुप्ता ने कहा कि जीएसटी की प्रस्तावित दरों को लेकर दिल्ली के व्यापारियों में नाराजगी है। करीब 50 वस्तुओं से जुड़े कारोबारी संगठनों ने जीएसटी दरों को अव्यवहारिक बताते हुए इसे कम करने की मांग की है।सीटीआइ के महासचिव राकेश यादव और रमेश आहूजा ने बताया कि ऑटो स्पेयर पार्ट्स को 18 फीसद, ट्रैक्टर पार्ट्स 12 फीसद, मार्बल 5 फीसद, इलेक्ट्रिकल आइटम 12 फीसद, हार्डवेयर 18 फीसद, सीमेंट 12 फीसद, टिंबर 5 फीसद, स्टेनलेस स्टील व कटलेरी 5 फीसद, नमकीन 5 फीसद, ब्राडेड बिस्किट 12 फीसद, अचार एवं मुरब्बा 5 फीसद, बैग 5 फीसद व सभी तरह के फुटवियर 5 फीसद के जीएसटी टैक्स स्लैब में रखने की मांग है।इसके अलावा ब्राडेड आटा, दाल व चावल के साथ ही झाड़ू, गोटा जरी, प्लास्टिक वेस्ट व कपड़ा को जीएसटी मुक्त रखने का सुझाव दिया गया है।

Kumar Associates

Soliciter & Advisor (Legal)

Delhi District Court & High court

Karanjeet Kumar (Advocate)

H.O. : 133-A Krishan Kunj Extn.

Laxmi Nagar, Delhi-110092

Mob :9999839708, 8527362212

इरफान खान अभिनय की अनूठी शैली के कारण दर्शकों का मन मोहने में कामयाब रहे हैं। वे जिस फिल्म से जुड़ते हैं, उससे दर्शकों को एक खास उम्मीद हो उठती है। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड मेकर्स का ध्यान आकर्षित करने में भी वो कामयाब हुए हैं। वो हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में कर चुके हैं। देश के साथ विदेश में भी काफी संख्या में उनके फैंस हैं। इरफान नियमित रूप से बॉलीवुड के दूसरे अभिनेताओं की फिल्मों के साथ हॉलीवुड की फिल्में देखते है। उनका कहना है कि दूसरे कलाकारों की फिल्मों से

प्रबंधन के क्षेत्र में कॅरियर

प्रबंधन चाहे घर का हो या किसी व्यवसाय या कंपनी का स्वयं में एक बड़ा काम है। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने वाले कम ही लोग होते हैं। प्रबंधन का काम जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही सम्मानजनक भी है। नेतृत्व क्षमता और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की हसरत रखने वाले युवा मानव संसाधन प्रबंधन को कॅरियर के तौर पर अपना सकते हैं।

मानव संसाधन प्रबंधक के अंतर्गत कार्यों को बेहतर तरीके से करने के गुर सिखाए जाते हैं। जिनमें कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखना, उनमें टीम वर्क की भावना पैदा करना, काम करने का आदर्श माहौल तैयार करना, कंपनी को लाभ की स्थिति में बनाए रखना और कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए नए–नए अनुसंधान करना शामिल है।मानव संसाधन प्रबंधन में कॅरियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी की तर्कशक्ति परीक्षण अच्छा होना चाहिए साथ ही गणित और सामान्य ज्ञान पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मानव संसाधन प्रबंधन डिप्लोमा के लिए प्रवेश की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कैट और मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा मैट के जरिए अभ्यर्थी का चयन होता है। पहले लिखित परीक्षा होती है और इसमें उत्तीर्ण लोगों का तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान और निर्णय शक्ति पर केंद्रित साक्षात्कार होता है। इन सभी में सफल अभ्यर्थी को संस्थान में प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रम में डिप्लोमा अवधि में छात्रों की व्यवहारिकता पर ज्यादा जोर दिया जाता है।

fQYe txr

दीपिका के साथ फिर नजर आएंगे इरफान खान

उन्होंने काफी कुछ सीखा है। इरफान खाली डॉयलाग बोलने या सिर्फ पर्दे पर दिखने को एक्टिंग नहीं मानते। इरफान अपने किरदारों के जरिये हमेशा अपना सच खोजने की कोशिश करते नजर आते हैं। भारतीय सिनेमा बदल रहा है। लीक से हटकर फिल्में बन रही हैं। 'पीकू' जैसी फिल्मों में लाइट रोमांटिक रोल में इरफान को काफी पसंद किया गया। 'पीकू' के बाद एक बार फिर इरफान खान और दीपिका की जोड़ी विशाल भारव्दाज की अगली फिल्म में नजर आएगी। यह फिल्म डॉन रहीमा खान उर्फ सपना दीदी पर आधारित होगी, जिसने दाऊद को मारने की साजिश रची थी। इरफान एक लोकल गैंगस्टर का किरदार निभाएंगे। 'फाइंडिंग फैनी' निर्देशक होमी अदजानिया की फिल्म में इरफान खान और सुशांत सिंह नजर आएंगे। इरफान और तब्बू बालाजी मोशन पिक्चर्स की अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही फिल्म में उम्र दराज सिख रोमांटिक कपल के तौर पर नजर आएंगे।

इसके अलावा इरफान खान 2007 में आई 'लाइफ इन मेट्रो' के सीक्वल का हिस्सा होंगे। इरफान खान आम तौर पर डार्क किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं।

वे दीपिका और ऐश्वर्या जैसी बेहद ,खूबसूरत एक्ट्रेसों के साथ रोमांटिक किरदार कर चुके हैं। तनुजा चंद्रा की एक फिल्म में चार नायिकाओं के साथ नजर आयेंगे। यह फिल्म रोड ट्रिप के बारे में है। इस यात्राा के दौरान इरफान मोहब्बत की बारीकियां समझाते हैं।

Ikjk Ip viMV fgnh ikf{kd lekpkj i= ikIr dju d fy,

Subscription From / InL;rk gr Qke

नाम : ....

पता : ....

शहर : ....पिन : ....

फोन : .... मोबाइल : ....

ईमेलः ....

समयावधि : एक वर्षः 100/–..............तीन वर्ष : 300/– ....

पांच वर्ष : 500/–...........आजीवन : 3000/– ....

भुगतान : नकद ....डीडी/चैक..........................

ukV % o"k ,d@rhu@ikp dh InL;rk d fy, MhMh@pd ij 50@&vfrfjDr cd pkt tkMdj nuk gkxkA

Qke IkQ IkQ Hkjdj Ikjk Ip viMV d uke MhMh@pd d Qke d IkFk fuEu ir ij Hkts ;k d'k vkfQI e tek djk,] Qke vki www.sarasach.com / join-us/ I dkih dj Idr gA

irk % 12@596] xyh ucj&2] oLV x: vxn uxj] fu;e Kku dt dkykuh] y{eh uxj] fnYyh&92

bl&ey & sarasach99@gmail.com, info@sarasach.com

ekckby % 999&000&4667 &7067 Qku% 011-65100636

अब आयोग रखेगा नजर बच्चों के शेल्टर होम पर

नई दिल्ली। बेसहारा बच्चों को आश्रय देने वाले शेल्टर होम पर बाल आयोग निगरानी रखेगा। दिल्ली के सभी बाल सुधार गृहों और शेल्टर होम का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने साथ जुड़े ऐसे सभी सुधार गृहों को सूचित कर दिया है।

रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी बच्चे के साथ यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो आयोग सीधे कार्रवाई कर सकेगा। आयोग ने पिछले पांच साल के रिकॉर्ड के साथ संचालकों को तलब भी किया है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग ने पांच टीमों का गठन किया है, जो जल्द ही काम शुरू करेंगी। आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने बताया कि शेल्टर होम और बाल सुधार गृहों का निरीक्षण किया जाएगा। कितने बच्चे, कितने समय से रह रहे हैं, इसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। दिल्ली में सरकारी और निजी मिलाकर तीस से अधिक शेल्टर होम एवं सुधार गृह हैं। हाल ही में कई शेल्टर होम और बाल सुधार गृहों ने अपने साथ अन्य संस्थाओं को जोड़ा है। कुछ ने पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण नई इमारतों में बच्चों को रखना शुरू कर दिया है। आयोग के पास हाल ही में कई संस्थाएं नया शेल्टर होम शुरू करने को लेकर पहुंची हैं। उनके प्रस्ताव को आयोग नहीं अभी पास नहीं किया है।उल्लेखनीय है कि शेल्टर होम और बाल सुधार गृहों की जानकारी आयोग के पास तो है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन वह नहीं करता था। स्थानीय प्रशासन एवं बाल विकास विभाग इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बाल आयोग को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने को कहा है।

डीयू के तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षक अपनी फरियाद लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर डीयू में तैनात 4500 तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग की। शिक्षकों की पदोन्नति, पेंशन, स्थायी नियुक्ति, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की समस्या, लाइब्रेरियन को शिक्षकों का दर्जा देने तथा वेतन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की माग भी राष्ट्रपति के समक्ष रखी।

माकन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डीयू तथा शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रही है। उच्च शिक्षा के बजट में 55 फीसद की कटौती की गई है, जिससे डीयू के करीब 4500 तदर्थ शिक्षको को नियमित नहीं किया जा रहा है। डीयू के नियम के अनुसार दस फीसद से ज्यादा तदर्थ शिक्षक नहीं होने चाहिए, जबकि इस समय इनकी संख्या लगभग 50 फीसद है। वर्ष 1977 से 2003 के बीच डीयू में तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया गया था। तीन हजार शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है।

फिजिकल एजुकेशन के करीब 2500 शिक्षकों को कर्मचारी की श्रेणी में डालने की कोशिश हो रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक की जाएं।

प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली प्रदेश प्रभारी पीसी चाको, इंडियन नेशनल टीचर्स कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विनी शकर, महासचिव एएम खान, पूर्व मंत्री किरण वालिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन शिक्षक संघ के सचिव डॉ. बेनू गुप्ता, शिक्षक समायोजन आदोलन के नेता डॉ. मनोज कुमार, कांग्रेस नेता मेहदी माजिद भी शामिल थे।

दिल्ली मेट्रो : पॉकेटमारी का ग्राफ तीन गुना बढ़ा

नई दिल्ली। यह तथ्य सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस साल अभी तक जेब काटने के मामले जो रिपोर्ट सीआईएसएफ ने सौंपी है, उसमें 77 फीसद महिलाएं हैं। चोरी का यह ग्राफ पिछले साल के मुकाबले तीन गुना बढ़ा है। जनवरी से मई तक के डेटा को देखें तो पॉकेटमारी में 77 फीसद महिलाएं पकड़ी गई हैं। सीआईएसएफ ने इस पर रोक लगाने के लिए पिछले महीने एक अभियान शुरू किया है। सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में सफर करते वक्त अपने सामान को लेकर कुछ ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक पकड़े गए 521 पॉकेटमारों में से 401 महिलाएं हैं। 148 पॉकेटमारों को यात्रियों की मदद से पकड़ा गया। महिला पॉकेट मार गैंग में काम करते हैं और अधिकतर वह अपने साथ बच्चों को लेकर चलते हैं। जिससे ध्यान बांटा जा सके। लोग बच्चे के साथ सफर कर रही महिला पर शक नहीं करते और इसी का फायदा वे उठाते हैं।इस महीने में बैश् की टीम ने 52 महिलाओं को पकड़ा है। इनसे गोल्ड जूलरी और कैश बरामद किया गया है। आरोपियों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

सीआईएसएफ का चोरी रोकने के लिए अभियान

1– स्पेशल टीम हर लाइन पर चोरी रोकने के लिए अभियान चलाती रहेगी। सबसे ज्यादा पॉकेट मारी की घटनाएं चांदनी चौक, शाहदरा, हुडा सिटी सेंटर, कीर्ति नगर, नई दिल्ली और तुगलकाबाद में होती हैं।

2– एक अफसर ने कहा कि जेब कटने की घटना की शिकायत और रिपोर्ट जरूर करें।

3– चोरी पर रोक लगाने के लिए बनी टीम में एक सब–ऑफिसर और एक कॉन्सटेबल होगा जो संदिग्धों पर हर तरह से नजर रखेगा। इनकी मदद के लिए ग्राउंड पर स्टाफ तैयार रहेगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआइ टीम पहुंची

नई दिल्ली । अपनों (कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास) के साथ विपक्ष के पहले झेल रही दिल्ली में सत्तासनी आम आदमी पार्टी सरकार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अंदरूनी झगड़ों में उलझी आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआइ टीम पहुंची।

हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में धांधली को लेकर भी सीबीआइ टीम मनीष के घर पर आई थी। वहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ये छापे टॉक टू एके कार्यक्रम में गड़बड़ी की जांच के लिए मारे गए हैं।

गौर करने वाली बात यह भी है कि मनीष सियोदिया के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो को आप के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए कई सबूतों के बाद भी ये कार्रवाई हो सकती है।

सीबीआइ के अधिकारियों ने मनीष के मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास ।ठ 17 पर कागजात खंगाले और फिर चले गए। वहीं, सीबीआइ ने एएनआइ को बताया कि मनीष के घर पर कोई छापा नहीं मारा गया है। सीबीआइ के मुताबिक, जांच के सिलसिले में वह कुछ जानकारी लेने मनीष सिसोदिया के घर पर गई थी।

कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो को आप के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए कई सबूतों के बाद भी ये कार्रवाई हो सकती है।

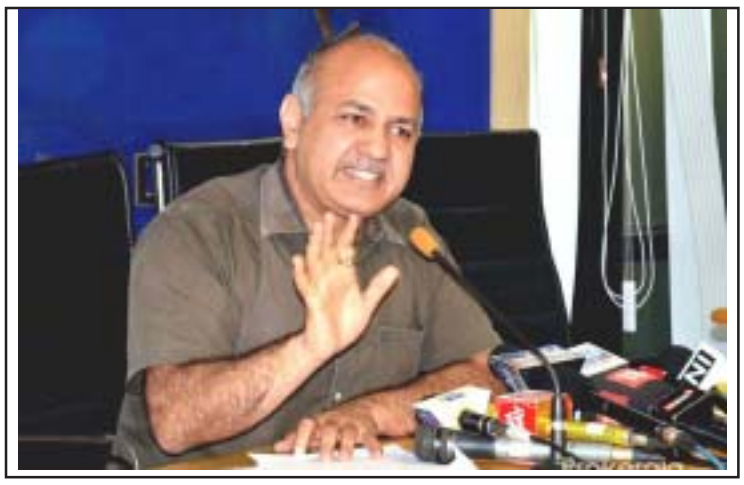

छापे को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, मनीष सिसोदिया के घर पर छापे पर ।।च के बागी और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है– केजरीवाल के भ्रष्टाचार का अंत शुरू।

मोहल्ला क्लीनिक विस्तार योजना खटाई में

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की अति महत्वाकांक्षी मोहल्ला क्लीनिक विस्तार की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के विस्तार के तहत 2018 तक एक हजार मोहल्ला क्लीनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। मगर अभी तक 150 ही बन सके हैं। स्थिति यह है कि अभी तक बने मोहल्ला क्लीनिक को लेकर नगर निगम सवाल उठा रहे हैं। नए बनने वाले मोहल्ला क्लीनिक के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि उनके पास जगह नहीं है। जिस पर मोहल्ला क्लीनिक खोले जा सकें। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी नाराज हैं।

उन्होंने इस योजना को जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि 2018 तक 1000 मोहल्ला क्लीनिक के लिए सरकार का लक्ष्य है।

मगर अभी तक मात्र 150 मोहल्ला क्लीनिक ही बन पाए हैं। 850 कहां बनेंगे। इसके लिए अभी तक जगह ही नहीं मिली है।

केजरीवाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह बनने वाले मोहल्ला क्लीनिक के लिए शीघ्र जगह उपलब्ध कराएं। इसके लिए शिक्षा विभाग, जल बोर्ड व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड आदि को जगह देने का आदेश जारी करें।

आम अभ्यर्थी की कोई सुनेगा?

यह मामला पीजीटी राजनीति विज्ञान (पोस्ट कोड 149/12,150/12,175/14 तथा 176/14) के शिक्षकों की भर्ती का है, जिसमें टियर–II परीक्षा में जमकर घोटाला हुआ है। जिसकी शिकायत अभ्यर्थी उपराज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक कर चुके हैं, और दोनों ने ही जांच के आदेश भी दिए, परंतु DSSSB के कानों पर जूं तक नही रेंग रही है। एक ओर योग्य अभ्यर्थी दर–दर भटक रहे हैं, वही दूसरी ओर गलत उत्तरों पर चुने गए लोगों को दिल्ली का शिक्षा निदेशालय भर्ती दे रहा है। अभ्यर्थी दिलशाद हमीद का कहना है कि DSSSB जब उप–राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक की नहीं सुन रहा है तो आम अभ्यर्थी की क्यों सुनेगा। ऐसे में न्याय के लिए, हम जायें तो जायें कहाँ !

शिकायत है

स्वामी मुद्रक, प्रकाशक व संपादक **सलीम अहमद** द्वारा मयंक ऑफसेट प्रोसेस 794/95, गुरू रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92 से मुद्रित व12/596, गली नंबर–2, वेस्ट गुरू अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92 से प्रकाशित।
संपादक : **सलीम अहमद**. सारा सच अपडेट पाक्षिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों व समाचारों की सहमति आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा.